नबीनगर में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन (500मे0वा0 2) की स्थापना

नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृति दी जानी है। मंजूरी और चालू परियोजनायें के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में बिहार की विद्युत विकास की आठवीं और नौवीं योजना में और अधिक क्षमता बढ़ाना आवश्यक नहीं पाया गया। आठवीं और नौवीं योजना अवधियों के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नबीनगर थर्मल पावर स्टेशन को पूर्वी क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है

दरभंगा और फोरबेसगंज के बीच मिसिंग लेटरल रोड़ लिंक का पूरा किया जाना

राष्ट्रीय राजमार्गों सहित केन्द्रीय क्षेत्रक सड़कों के लिए राशियों के अत्यन्त सीमित होने को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में जोड़ना संभव नहीं है।

बरौनी रिफाइनरी का विस्तार

बरौनी रिफाइनरी की वर्तमान संस्थापित क्षमता 3.3 मि० टन वार्षिक है। वहरहाल, कच्चे तेल की उपलब्धता 1990–91 में 2.4 मि. टन और 1991–92 में 2.3 मि. टन है। रिफाइनरी की और अधिक क्षमता विस्तार के लिए प्रस्ताव पर कम कच्चे तेल की आपूर्ति के कारण रिफाइनरी को वर्तमान क्षमता के लिए भी आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

पैट्रो-कैमिकल/एरोमैटिक कम्प्लेक्स

तकनीकी-आर्थिक कारणों से प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

अशोक पेपर मिल्स

बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि डालमिया समूह ने अशोक पेपर मिल्स को लेने में रूचि दिखाई है।

पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना

इस परियोजना के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को एक आशय पत्र जारी किया गया है।

मिनि स्टील काम्प्लेक्स

स्टील क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और कोई भी इच्छुक दक्ष, मिनि-स्टील संयंत्र में निवेश कर सकता है

रोहतास उद्योग

बिहार सरकार ने बी आई एफ आर की मंजूरी से रोहतास उद्योग को पुनर्स्थापन करने के लिए कदम उठाए हैं। रोहतास उद्योग के एसबेसटोल और वनस्पति इकाइयों को पहले ही पुनः चालू कर दिया गया है और इन्होंने उत्पादन आरंभ कर दिया है।

कैप्रोलेक्टम परियोजना

50,000 वार्षिक कैप्रोलेक्टम परियोजना के लिए एक आशय पत्र बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी किया गया है। इसके श्रीराम उद्योग समूह के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में लिए जाने की संभावना है।

बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए टेक्नालाजी मिशन की स्थापना

टेक्नालाजी मिशन पर जल संसाधन मंत्रालय के दृष्टिकोण पत्र पर सचिवों की समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया जिसने उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रु० उपलब्ध कराने का योजना आयोग को सुझाव दिया जिसमें से 70 करोड़ रु० जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय में उपलब्ध कराना था और 30 करोड़ रु० राज्य क्षेत्र का निधियों में से। इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति के निर्णय के अनुसार उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक स्टीयरिंग समिति गठित की गई थी। 20 लाख रु० की राशि मार्च, 1992 में जारी की गई थी। इस राशि का उपयोग प्रमाणपत्र राज्य सरकार से प्राप्त होना है। उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कोई स्कीम जी.एफ.सी.सी. के पास लंबित नहीं है।

Private Sector's participation in core Sector

3068. SHRI PRABHAKAR B. KORE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) has

called for active private sector's participation in core areas like defence, mineral, oil and coal; and

(b) if so, what action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Planning Commission has not received any such communication from Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(b) Does not arise.

रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य

3069. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गत दो दशकों के दौरान रोजगार के नये अवसरों की उपलब्धता की प्रतिशतता मे लगातर कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो सत्तर और अस्सी के दशक मैं रोजगार के नए अवसरों की उपलब्धत का प्रतिशत क्या था ;

(ग) क्या सरकार ने नब्बे के दशक के दौरान इस प्रतिशत में वृद्धि करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा रोजगार तथा बेरोजगारी पर किये गये व्यापक सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि सामान्य रोजगार की मुख्य स्थिति को औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1977-78 से 1983 के बीच 2.10% और वर्ष 1983 से 1987-88 के बीच 1.77% रही। योजना अवधि के दौरान, आठवीं योजना (1992-97) में प्रतिवर्ष 2.6 से 2.8 प्रतिशत के आसपास औसत रोजगार वृद्धि की परि-कल्पना की गई है।

Projects of Arunachal Pradesh pending for clearance

3070. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what are the names of the projects of Arunachal Pradesh pending with the Central Government for final clearance and;

(b) the details of the projects and the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) No poject sent by the Government of Arunachal Pradesh is pending for final clearance from the Planning Commission.

Financial Assistance for Development of Kuchh and Saurashtra

3071. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government have provided any financial assistance for the Development of Kuchh and Saurashtra areas of Gujarat State;

(b) if so, the financial assistance given to the State for this purpose during each of the last three years; year-wise;

(c) whether Government propose to increase the financial assistance;